

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने किया दौरा, केंद्र से साझेदारी का बनेगा प्रस्ताव

उज्जैन में कैंपस के लिए आइआइटी को आर्थिक सहायता देगी सरकार



पत्रिका

एक्स-
क्लूसिव

अभिषेक वर्मा

patrika.com

इंदौर. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी), इंदौर के उज्जैन में प्रस्तावित सैटेलाइट कैंपस को खुलवाने के लिए राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। सरकार केंद्र के साथ मिलकर साझेदारी में यह कैंपस शुरू करने का प्रस्ताव बनाएगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शैलेंद्र सिंह ने आइआइटी का दौरा भी किया है।

दिसंबर 2021 में आइआइटी ने उज्जैन में सैटेलाइट कैंपस शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया था। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा भी कर दी। विक्रम यूनिवर्सिटी परिसर में सत्र 2022-23 से ही कैंपस लगाने की तैयारी शुरू हुई। इस बीच आइआइटी में प्रशासनिक बदलाव हुए। संस्थान पर पहले से ही चल रहे कर्ज का



कौशल विकास के कोर्स भी

आइआइटी को आर्थिक मदद हासिल करने के लिए ऐसे कोर्स संचालित करना होंगे जिनमें स्थानीय छात्रों को सीधा लाभ मिले। इसलिए उज्जैन कैंपस से प्रमुख कार्यक्रम के साथ कौशल-विकास कोर्स चलाने की भी सहमति है।

हवाला देते हुए इस सत्र से सैटेलाइट कैंपस के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल लिया गया। सैटेलाइट कैंपस के लिए करीब ₹500 करोड़ का खर्च आएगा, जबकि आइआइटी पर पहले ही केंद्र के ₹350 करोड़ बकाया हैं।

बजट के लिए चर्चा जारी

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जब संस्थान के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि आइआइटी अपने संसाधन से उज्जैन में सैटेलाइट कैंपस स्थापित नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने कहा, राज्य सरकार शिक्षा मंत्रालय से चर्चा कर रही है ताकि केंद्र और राज्य मिलकर सैटेलाइट कैंपस की स्थापना के लिए बजट जुटा सकें।